भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †4903
दिनांक 01.04.2025 को उत्तरार्थ

जिला संसाधन केंद्र

†4903. डॉ. राजीव भारद्वाज:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जिला संसाधन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश के किन-किन जिलों में उक्त केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और
(ग) उक्त केन्द्रों की स्थापना के लिए आबंटित की जाने वाली प्रस्तावित कुल धनराशि कितनी है और तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) से(ग) जी हां। मंत्रालय वित्तीय वर्ष2022-23 से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान(आरजीएसए) की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों(ईआर) और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं(पीआरआई) को मजबूत बनाना है ताकि वे नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए अपनी शासन क्षमताओं का विकास कर सकें और ग्राम पंचायतों को प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बना सकें। आरजीएसए योजना के तहत मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जिला पंचायत संसाधन केंद्र(डीपीआरसी) सहित क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए संस्थागत प्रणाली स्थापित करने के लिए भी सहायता प्रदान कर रहा है। इस योजना के तहत, हिमाचल प्रदेश के चंबा और लाहौल स्पीति जिलों के लिए आरजीएसए योजना के लागत मानदंडों के अनुसार2 करोड़ रुपये प्रत्येक की लागत से2 डीपीआरसी के निर्माण को मंजूरी दी गई है।

***